

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

प्रमारी मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 3 अगस्त, 2006

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में एन.पी.वी., भूमि प्रतिकर के भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग-1 के पत्र सं० 908(1)/XXVII (1)/2006 दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के क्रम में आपके पत्र संख्या-876/25 बजट(प्रतिकर)/2005-06, दिनांक 17.05.2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि के अधिग्रहण एवं भूमि प्रतिकर के भुगतान आदि हेतु रुपये 1500 लाख (रु० पन्द्रह करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- एन०पी०वी० एवं भूमिप्रतिकर का भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान वर्षवार वरियता के आधार पर किया जायेगा। अर्थात् सबसे पुरानी देयता का भुगतान सबसे पहले तथा उसके बाद के वर्ष का उसके बाद तथा इसी वर्ष की सड़कों का सबसे अन्त में किया जायेगा, तथा वरियता के आधार पर जैसे-2 देयताओं का भुगतान किया जायेगा उसकी सूचना शासन को मासिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। विभागाध्यक्ष के द्वारा उक्त देयों के भुगतान हेतु निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि से परिपक्व दावों का भुगतान अपने स्तर से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3- भूमिप्रतिकर भुगतान में मा० न्यायालयों एवं विधायिका में आश्वस्त किये गये प्रकरणों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर प्रथम वरियता में किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन.पी.वी. भुगतान हेतु वन विभाग को किया जाये।

5- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कय की गई भूमि का शीघ्र विभाग के नाम हस्तान्तरण कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का या अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण साख सीमा के माध्यम से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9- यदि धनराशि स्वीकृत करने के बाद भी पूर्व के वर्षों की देयता रहती है और धनराशि शासन की समर्पित की जाती है तो इस हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। अतः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग व दायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय साख परिव्यय के अधीन, स्थापित नियमों एवं प्रक्रिया के अधीन ही सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी परिपक्व रखे प्रस्तर-2 की वरियता के अनुसार तत्काल भुगतान सुनिश्चित करके इसका मासिक व्यय विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जाय।

प्रमाण

10- इस संबध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सडकें-आयोजनागत- 800-अन्य व्यय-05 सडक/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेंगा ।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं०- 382 /XXVII(2)/06, दिनांक, 01 अगस्त, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- 2227
(1)/III(2)/05, तददिनांक ।

- 1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 2- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स माजरा, देहरादून ।
- 3- आयुक्त गढवाल/कुमायू मंडल, पौड़ी/नैनीताल ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
- 5- मुख्य अभियन्ता, गढवाल/कुमायू क्षेत्र, लो०नि०वि०, पौड़ी/ अल्मोड़ा ।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन ।
- 8- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तरांचल शासन ।
- 9- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल देहरादून ।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तरांचल शासन
- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
प्रदीप सिंह रावत
(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।